(b) what is the area of the public land encroached during 1989 and since the beginning of 1990 till date;

(c) what are the business centres in Delhi with maximum encroachment on roads and footpaths; and

(d) what steps have been taken/ proposed to be taken by Government to curb the growing problem of illegal occupation of public land and unauthorised encroachment on footpaths and roads?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन

1158. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब बनाई गई थी और इस पर वित्तीय वर्ष 1989–90 के अन्त तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस योजना के क्रियान्वयन का कार्य अभी तक भी प्रारम्भ नहीं हो पाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) सन 1959 में तैयार किए गये दिल्ली के मास्टर प्लान के मसौदे में उल्लिखित सिफ़ारिशों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की स्थापना 1961 में की गयी थी और इसका पुनर्गठन 1973 में किया गया था। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के परिणामस्वरूप यह सांविधिक बोर्ड अस्तित्व में आया। इस बोर्ड में एक सांविधिक क्षेत्रीय योजना 2001–एन०सी०आर० तैयार की थी; इसे 23 जनवरी, 1989 से लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष, 1989–90 के अन्त तक केन्द्र सरकार द्वारा तथा भाग लेने वाले राज्य सरकारों द्वारा किया गया कुल व्यय 128.08 करोड़ रुपये हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Construction of godowns by Central Warehousing Corporation

1159. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Central Warehousing Corporation have constructed any godown at Falta, West Bengal; and

(b) if not, the reasons for which work has not been started so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) and (b) Yes, Sir. Central Warehousing Corporation had constructed a capacity of 2000 Mts. at Falta, West Bengal during 1987.

Interest free loan under IRDP

1160. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to give interest free loan under IRDP schemes instead of giving subsidies; and

(b) whether Government are aware that the subsidy portion is being shared by the agencies involved in granting these loans?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA): (a) Loans under the IRDP are given by the Credit Institutions, Government of India and the State Government together provide subsidy under the programme. A proposal to replace the present subsidy by an interest free loan was considered. For various reasons, it has been decided to continue the present practice.

(b) All possible efforts are made through the State Governments to prevent mis-utilisation of subsidy.

गेहूं, चावल और चीनी के भण्डार की स्थिति

1161. डा० रत्नाकर पाण्डेय : : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में घरेलू खपत के लिए गेहूं, चावल और चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो गत 6-7 महीनों में बाजार में इनके मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष के दौरान समर्थन मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि करने और निर्गम मूल्यों में बढ़ोतरी करने के कारण 21-7-90 को समाप्त हुए पिछले छः महीनों के दौरान चावल और गेहूं के थोक मूल्यों के सूचकांक में केवल क्रमशः 82 प्रतिशत तथा 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चीनी के सूचकांक में मामूली गिरावट (-0.1 प्रतिशत) आई है।

15-सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन अल्पसंख्यकों का कल्याण

1162. डा० अबरार अहमद खान : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु लागू किये जा रहे 15-सूत्रीय कार्यक्रम से अब तक अल्पसंख्यक लोगों का कितना कल्याण हुआ है तथा इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए है और दरअसल में यह कार्यक्रम किन-किन राज्यों में लागू किया गया था इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम को सक्रिय एवं प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या उन अधिकारियों को दंडित किया गया है जिन्होंने इस कार्यक्रम की उपेक्षा की है और क्या इस प्रकार का दंड दिये जाने का कोई प्रावधान है; और

(ग) राजस्थान में उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जहां इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का आंकलन करने के लिए गत 8 महीनों के दौरान राज्य और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की गई ; उन बैठकों की तिथियां क्या-क्या हैं और उनके क्या निष्कर्ष निकले ; इस संबंध में सवाई माधोपुर जिले के बारे में ब्यौरा क्या है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) उन लाभों का परिमाण न कठिन है, जो 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं। इससे अल्पसंख्यकों की समस्याओं के संबंध में निश्चित रूप से जागरूकता पैदा हुई तथा फिर ठोस कार्यक्रम बने हैं।

तथापि 1-1-89 से 31-3-90 तक की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला एक